

# फेडरेशन ऑफ क्लास-1 ऑफीसर्स एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन, आल इंडिया एलआईसी एम्पलाईज फेडरेशन

## मध्य क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम

प्रिय साथियों ,

दिनांक 16 जनवरी 2022

हम यहाँ एलआईसी के संयुक्त मोर्चे की यूनियनों/एसोसिएशनों द्वारा 19 जनवरी 2022 को 'सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ--एलआईसी को मजबूत बनाओ दिवस' के रूप में मनाये जाने संबंधी जारी परिपत्र का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपनी मध्य क्षेत्र की सभी इकाइयों से अनुरोध करते हैं कि संयुक्त मोर्चा के हमारे सहयोगियों के साथ तालमेल कर इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजित करें।

अभिवादन सहित

आपके साथी

के पी गुप्ता

क्षेत्रीय महासचिव

फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास 1  
ऑफिसर्स एसोसिएशन

राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी

सहसचिव, प्रभारी क्षेत्रीय महासचिव

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस  
फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया

डी आर महापात्र

महासचिव

सेंट्रल जोन इंश्योरेंस  
एम्प्लॉइज एसोसिएशन

सुबीर भारतीय

महासचिव

ऑल इंडिया एलआईसी  
एम्प्लॉइज फेडरेशन

मध्य क्षेत्र

## 19 जनवरी 2022--एलआईसी के राष्ट्रीयकरण दिवस को 'सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ--एलआईसी को मजबूत बनाओ' दिवस के रूप में मनाएं।

19 जनवरी का दिन एल आई सी के कर्मचारियों व अधिकारियों हेतु एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। साढ़े 6 दशक पूर्व 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की ओर पहला कदम बढ़ाया गया था। तत्कालीन सरकार ने जीवन बीमा (आपातकालीन प्रावधान) अध्यादेश 1956 की घोषणा कर 154 भारतीय बीमाकर्ताओं, 16 विदेशी बीमाकर्ताओं तथा 75 भविष्यनिधि सोसायटियों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था। 20 जनवरी 1956 को भारत सरकार द्वारा नियुक्त 42 परिरक्षकों द्वारा समस्त जीवन बीमा कंपनियों का कार्यभार संभाल लिया गया था। 19 जनवरी 1956 से 31 अगस्त 1956 की मध्य की अवधि का उपयोग विभिन्न बीमाकर्ताओं को राज्य के स्वामित्व वाले एकल निगम के अंतर्गत लाने की तैयारी हेतु किया गया था। इसलिए 19 जनवरी का दिन देशभर के बीमा कर्मचारियों व अधिकारियों का न केवल प्रिय दिवस है, अपितु यह एलआईसी को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखने हेतु आश्वस्त का दिन है, यह दिन हमारे विश्वास और प्रतिबद्धताओं को मजबूत बनाने का दिन है, यह नये जोश के साथ आगे बढ़ने का दिन है।

बीमा के राष्ट्रीयकरण का विचार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग था। सन् 1931 के कांग्रेस के करांची अधिवेशन ने यह कहकर कि 'लाखों भूखों के लिये राजनीतिक आजादी को वास्तविक आर्थिक आजादी से जोड़ना होगा' --इसका स्वर तय कर दिया था। संविधान का निर्माण करनेवाली सभा ने 1948 में एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राज्य को बीमा व्यवसाय का प्रबंध करना चाहिये। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ बी आर अंबेडकर स्वयं इस हेतु उत्सुक थे कि 'बीमा का राष्ट्रीयकरण कर यह सरकार द्वारा प्रबंधित होना चाहिये।'

जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण को हड़बड़ी में, गुप्त रूप से तथा जनता की जानकारी में लाये बिना किये जाने के कुछ आसन्न कारण थे। निजी बीमा कंपनियों के मालिकों की लूट व डकैती इतने बड़े पैमाने पर पहुँच गई थी जिसके चलते भारत के शासकों को जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के निर्णय को बारीकी से संरक्षित रहस्य की भाँति गुप्त रखना पड़ा था। सरकार को लग रहा था कि अध्यादेश जारी होने के थोड़े से संकेत मिलने पर निजी कंपनियों के

मालिक अंतिम समय में धाँधली का सहारा ले सकते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि 1945-55 के दशक के दौरान 25 बीमाकर्ताओं ने अपने व्यवसाय का परिसमापन कर दिया था और इतनी ही संख्या में दूसरे बीमाकर्ताओं को अपना व्यवसाय अन्य कंपनियों को स्थानांतरित करना पड़ा था। जो कंपनियां इन सबसे बचे रहने में कामयाब रही, उनमें से 75 कंपनियां अपने पिछले वर्ष 1953-54 के मूल्यांकन पर किसी भी बोनस की घोषणा करने में असमर्थ थीं। यह कैसी त्रासादी थी कि जिस वक्त कंपनियां भारी नुकसान उठा रही थी, उनके मालिक घृणित रूप से विलासिता में लिप्त थे।

इस मुश्किल दौर में 1 सितंबर 1956 को बहुत सारी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ एलआईसी अस्तित्व में आई थी। राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ सी डी देशमुख ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था-- 'हम गतिशीलता और उत्साह को एक साथ जोड़ते हुए एक ऐसा संगठन बनायेंगे जो पूरे देश के हर तबके के लोगों को बीमा प्रदान करने तथा उनकी बचतों को एकत्रित करने में सक्षम होगा तथा उसी वक्त उन्हें कुशल सेवा के साथ - साथ पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करेगा।'

उस वादे के अनुरूप एलआईसी ने विगत कुछ वर्षों में न केवल जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, वरन राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिये समुदाय की बचत को चैनलाईज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वर्ष 1956 में अपनी स्थापना के पश्चात से ही एलआईसी ने लाखों भारतीयों का विश्वास और सद्भावना अर्जित किया है और कई मील के पत्थर पार किये हैं। एलआईसी ने जीवन बीमा व्यवसाय के विभिन्न मोर्चों पर अभूतपूर्व प्रदर्शन का रिकार्ड स्थापित किया है। वर्ष 1956 में 5 करोड़ रुपये की मामूली राशि के साथ जीवन बीमा व्यवसाय का आरंभ करने वाली एलआईसी आज 38 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की खगोलीय रूप से विराट परिसंपत्ति की मालिक है। ग्राहक आधारवाली पालिसियों के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसके पास 40 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इसमें 30 करोड़ व्यक्तिगत पालिसियाँ चालू हालत में हैं तथा अन्य 12 करोड़ लोग समूह बीमा पालिसियों के अंतर्गत संरक्षित हैं। जीवन बीमा व्यवसाय में 2 दशकों से अधिक की प्रतिस्पर्धा के बाद भी उद्योग में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी के साथ आज एलआईसी खड़ी है। एलआईसी आज लाखों भारतीयों की पसंदीदा बीमा कंपनी है। दुर्भाग्य से सार्वजनिक क्षेत्र के इस बेहतरीन संस्थान को आईपीओ और शेयर बाजार में सूचीबद्धता के नाम पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जनता के प्रचंड बहुमत द्वारा जबरदस्त विरोध किए जाने के बावजूद सरकार पूरी ताकत से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जीवन बीमा की पालिसी की ऑनलाइन बिक्री जैसे नए व्यापार चैनलों ने हमारे विशाल एजेंसी बल के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। एलआईसी के अलावा भी बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को 'आत्मनिर्भर भारत' की आड़ में निजीकरण और विनिवेशीकरण हेतु तैयार किया गया है।

इस परिदृश्य में 30 दिसंबर 2021 को संपन्न संयुक्त मोर्चा की बैठक ने 19 जनवरी 2022 को 'सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ--एलआईसी को मजबूत बनाओ दिवस' मनाने का आव्हान किया है। हम पूरे देश भर में अपनी इकाइयों से आव्हान करते हैं कि इस अवसर पर संयुक्त रूप से उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करते हुये सार्वजनिक क्षेत्र में एलआईसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें।

### क्रान्तिकारी अभिवादन सहित...

आपके साथी

-सही-

( एस. राजकुमार )

महासचिव

फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास-1

आफीसर्स एसोसियेशन

-सही-

( विवेक सिंह )

महासचिव

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस

फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया

-सही-

( श्रीकांत मिश्रा )

महासचिव

ऑल इंडिया इंश्योरेंस

एम्पलाईज एसोसियेशन

-सही-

( राजेश कुमार )

महासचिव

ऑल इंडिया एलआईसी

एम्पलाईज फेडरेशन

**Say No to IPO in LIC**  
**Save Public Sector, Strengthen LIC**